नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 018
दि. 18.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

गुजरात में पूरी कैबिनेट बदली, BJP ने मिशन 2027 के लिए नए समीकरण साधने की तैयारी की

(जीएनएस)। गांधीनगर। बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक हलचल के बीच गुजरात ने राजनीतिक सुर्खियों में जगह बना ली है। भाजपा ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली पूरी कैबिनेट बदल दी। गुरुवार को सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और शुक्रवार को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ। इस नए मंत्रिमंडल में कुल 26 विधायक मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 19 नए चेहरे हैं और 3 महिलाएं शामिल हैं। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी इस कैबिनेट का हिस्सा बनी हैं।

विशेष रूप से इस नए मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर खास ध्यान दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 8 मंत्री पटेल समुदाय से हैं। इसके अलावा 8 OBC, 3 SC, 4 ST और 3 महिलाएं मंत्री बनी हैं। इसमें दो क्षत्रिय, एक ब्राह्मण और एक जैन भी शामिल हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम बीजेपी की 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी नए समीकरणों की पड़ताल करने के साथ-साथ युवा और नए नेताओं को जनता के करीब लाने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी के लिए यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी है। गोपाल इटालिया के नेतृत्व में AAP ने सौराष्ट्र और आदिवासी बेल्ट में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, जिससे बीजेपी को चुनौती मिली है। नए मंत्रिमंडल में इन क्षेत्रों के नेताओं को शामिल कर पार्टी ने रणनीतिक रूप से अपने समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की है। नई कैबिनेट में हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अर्जुन मोढ़वाडिया को मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा 19 नए नेताओं को मौका मिला है, ताकि उन्हें जनता से सीधे जुड़ने और क्षेत्रीय मुद्दों को समझने का अवसर मिले। सूत्रों के अनुसार, गुजरात में इस बड़े फेरबदल की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बनाई गई। नई दिल्ली में राज्य नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में कैबिनेट विस्तार और संगठन में नए चेहरे शामिल करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने खास तौर पर यह निर्देश दिया कि नए मंत्री जनता से तुरंत संपर्क करें और उनकी जिम्मेदारियों की शुरुआत प्रभावशाली ढंग से करें। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह कैबिनेट फेरबदल केवल शॉर्ट टर्म सुधार नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। पार्टी नए नेताओं को जनता के बीच सक्रिय करने के साथ ही पुराने नेताओं की वापसी का रास्ता भी बना रही है। इस रणनीति का उद्देश्य गुजरात में भाजपा का मजबूत गढ़ और आगामी विधानसभा चुनावों में व्यापक समर्थन सुनिश्चित करना है।

इस प्रकार गुजरात ने राजनीतिक सर्जरी के रूप में अपनी पूरी कैबिनेट बदलकर एक नया राजनीतिक समीकरण साधा है, जो राज्य में बीजेपी की ताकत और मिशन 2027 की दिशा को नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है।

पाकिस्तान-स्तान सीमा विवाद: शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को दिया स्पष्ट अल्टीमेटम

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को अफगानिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि हालिया सीमा पर झड़पों के बाद बातचीत तभी संभव है जब अफगान पक्ष पाकिस्तान की शर्तों को गंभीरता से माने। प्रधानमंत्री ने संघीय मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि गेंद अफगानिस्तान के पाले में है और अगर वे ईमानदारी और गंभीरता से बातचीत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है।

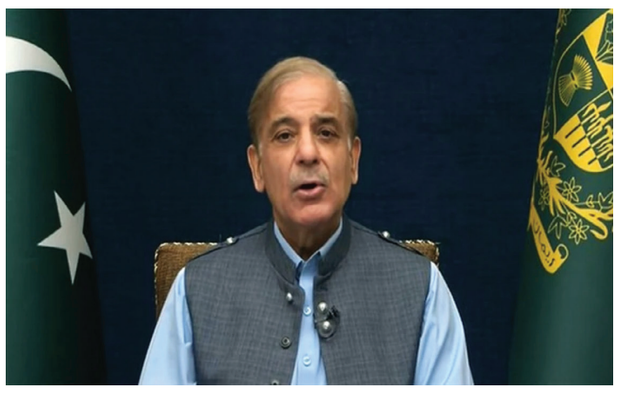

पिछले सप्ताह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें कई सैनिक और नागरिक प्रभावित हुए। दोनों देशों ने बुधवार को कतर की मध्यस्थता में 48 घंटे का अस्थायी युद्धविराम घोषित किया, जो 15 अक्टूबर की शाम से लागू हुआ। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि यह युद्धविराम स्थायी समाधान के लिए पहला कदम है, लेकिन केवल शर्तों को पूरा किए जाने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह केवल समय बिताने के उद्देश्य से किया गया, तो पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के अधिकारी कई बार काबुल गए और सौहार्दपूर्ण बातचीत की कोशिश की, लेकिन अफगान पक्ष की असंवेदनशीलता के कारण समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कतर सहित कई सहयोगी देश स्थिति को सामान्य बनाने और मध्यस्थता के प्रयास कर रहे हैं। शहबाज ने यह भी कहा कि स्थायी समाधान में अफगानिस्तान की भूमि से आतंकवादियों का सफाया शामिल होना चाहिए, ताकि भविष्य में अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए न किया जा सके।

शहबाज ने सीमा पर झड़पों के दौरान पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में कई जवानों की शहादत के बावजूद यह कदम आवश्यक था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा रहेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहबाज का यह कदम न केवल अफगानिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। उनका अल्टीमेटम इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब केवल संवाद की शर्तों के आधार पर ही किसी समझौते को मानने के लिए तैयार है।

केंद्र ने लेह हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान को सौंपा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसक झड़पों की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए। यह कदम प्रदर्शनकारी समूहों की प्रमुख मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हिंसा की घटना में 1999 के करगिल युद्ध में भाग लेने वाले एक सैनिक सहित चार लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग घायल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान को इस जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग को हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था के बिगड़ने, पुलिस कार्रवाई और उसके परिणामस्वरूप हुई जान-माल की हानि की परिस्थितियों की पूरी पड़ताल करनी होगी। आयोग में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार न्यायिक सचिव के रूप में काम करेंगे, जबकि आईएएस अधिकारी तुषार आनंद आयोग के प्रशासनिक सचिव होंगे। घटना के समय लेह में प्रदर्शनकारी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें चार नागरिकों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए।

नासिक में तेजस MK-1A की पहली उड़ान: भारत की वायु शक्ति को नया आत्मनिर्भर मुकाम

(जीएनएस)। नासिक। भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन तब आया जब तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने पहली बार नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की तीसरी उत्पादन लाइन से सफल उड़ान भरी। यह उड़ान न केवल भारतीय विमानन उद्योग की तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है, बल्कि देश की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और आधुनिक वायु शक्ति को नई दिशा देने का प्रतीक भी बन गई है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय का गर्व बढ़ा दिया है और यह हमारे सैन्य बलों की परिचालन तत्परता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

तेजस MK-1A को विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के पुराने मिग-21 विमानों की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। यह विमान 4.5 पीढ़ी का बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता,

उन्नत एवियोनिक्स, एईएसए रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसके अलावा, यह विमान जमीनी हमले, समुद्री हमले और टोही अभियानों के लिए पूरी तरह सक्षम है, जिससे यह भारतीय वायुसेना की विविध जरूरतों को पूरा कर सके। तेजस MK-1A की खासियत इसकी 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री और बहु-भूमिका हथियार समूह में निहित है। इसके उन्नत हथियार और पेलोड विकल्प इसे किसी भी चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए सक्षम बनाते हैं। यह विमान पुराने विमानों की जगह लेकर स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाने और भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता में वृद्धि करने में मदद करेगा। तीसरी उत्पादन लाइन के माध्यम से एचएएल का वार्षिक उत्पादन 16 से बढ़कर 24 जेट हो जाएगा, जिससे वायुसेना की मांग को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2025 को भारतीय वायुसेना के लिए 62,000 करोड़ रुपये की लागत से 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस कदम को युद्ध की तैयारी बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया और कहा कि नए विमानों की तत्काल उपलब्धता से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एचएएल के अधिकारियों ने भरोसा जताया कि उत्पादन प्रणाली के स्थिर होने और एकीकरण संबंधी चुनौतियों के समाधान के बाद ये विमान समय पर वायुसेना को प्रदान किए जाएंगे।

तेजस MK-1A की इस सफल उड़ान ने भारतीय एयरोस्पेस उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया है। यह केवल एक विमान नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक बढ़त, सुरक्षा की नई संभावनाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह विमान देश की वायु शक्ति में नई ऊर्जा भरते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र ने मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट की कड़ी निंदा की

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने मेडागास्कर में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट की कड़ी निंदा की है और संवैधानिक व्यवस्था व कानून के शासन की तत्काल वापसी की अपील की है। यह कदम उस समय आया है जब सेना के कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने देश की सत्ता अपने हाथ में लेने के तीन दिन बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की घोषणा की। सैन्य तख्तापलट के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए देश छोड़कर भाग गए हैं। अभी उनकी स्थिति अज्ञात है। रैंड्रियनिरिना ने उच्च संवैधानिक न्यायालय में आयोजित एक समारोह में अपने "पुनर्स्थापित" राष्ट्रपति के रूप में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि यह कदम तीन सप्ताह से चल रहे सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उठाया गया, जिनमें देश के असंतुष्ट युवा मुख्य रूप से शामिल थे।

इन प्रदर्शनों में युवाओं ने सरकारी सेवाओं की विफलता, बढ़ती गरीबी और अवसरों की कमी को लेकर विरोध जताया। साथ ही, उन्होंने अभिजात वर्ग में फैले भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। इन युवाओं ने अपने आंदोलन का नाम 'जेन जेड मेडागास्कर' रखा और व्यापक रूप से संगठित होकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन किए।

मेडागास्कर के इस हालात के बाद अफ्रीकी संघ ने देश को निलंबित कर दिया है। कर्नल रैंड्रियनिरिना ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता स्थिरता और प्रशासनिक नियंत्रण को बहाल करना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने इस सैन्य अधिग्रहण को पूरी तरह अस्वीकार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संवैधानिक व्यवस्था जल्दी बहाल नहीं हुई, तो मेडागास्कर को राजनीतिक और आर्थिक रूप से गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।

यह मामला नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता में बदलाव के घटनाक्रमों की श्रृंखला में जुड़ता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चेतावनी स्वरूप माना जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताकतवर समूहों द्वारा बाधित किए जाने की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए।

भारत-मिस्र संबंधों में नई मजबूती: पीएम मोदी ने मिस्र के विदेश मंत्री से की महत्वपूर्ण वार्ता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को "एक सच्चा मित्र" बताते हुए गाजा शांति समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। यह मुलाकात मिस्र के विदेश मंत्री की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुई, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी लगातार मज़बूत हो रही है और यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि पूरे साझा क्षेत्र और मानवता के लिए लाभकारी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि गाजा शांति समझौते में मिस्र के योगदान के लिए वे राष्ट्रपति सीसी के आभारी हैं। वहीं, विदेश मंत्री डॉ. अब्देलती ने पहली रणनीतिक वार्ता के दौरान साझेदारी की पूरी क्षमता को उजागर करने की दोनों नेताओं की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया और कहा कि यह समझौता जून 2023 में हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी का परिणाम है।

इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार साझा किए, जिसमें पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करना शामिल था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों को प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने का अवसर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सीसी ने हाल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी एकजुटता दिखाई और तत्काल संवाद किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और मिस्र वैश्विक दक्षिण की प्रगति और विश्व मामलों में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगी बल्कि भारत की पश्चिम एशियाई राजनीति में स्थायी भूमिका को भी मजबूती प्रदान करेगी। यह कदम भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

जन-संवाद की सुबह, फाइल-मंथन की सांझ

पहली नजर में बड़े पद की चमक-दमक का अपना सम्मोहन होता है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी-जवाबदेही व विपरीत चुनौतियों में सामंजस्य बैठाना कांटों का ताज पहनने जैसा ही होता है। अंतहीन जन-अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही कठिन होता है। वैसे किसी सत्ता का एक साल बहुत लंबी अवधि नहीं होती। उसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन करना भी जल्दबाजी ही कही जाएगी, लेकिन इससे किसी नेतृत्व या सरकार की दिशा-दशा को बोध तो हो जाता है। कमोबेश, यह कसौटी हरियाणा में एक साल पूरा कर रही नायब सैनी सरकार के लिये भी है। सामाजिक न्याय के समीकरण संतुलन की कवायद के क्रम में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले नायब सैनी की इस पद पर ताजपोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद रही है। जब नरेंद्र मोदी चंडीगढ़-हरियाणा में संगठन का दायित्व निभा रहे थे, तो सैनी उनके कार्यालय सहयोगी थे। इस मायने में बिना राजनीतिक व समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि के राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने को एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी सदाबहार मुस्कान-विनोदप्रियता के कायल रहे हैं। वे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान सार्वजनिक रूप से देते नजर आते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेने से भी वे नहीं चूके। वैसे तो उनके एक साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां सामने आती-जाती रही हैं, लेकिन हाल ही में एडीजीपी वाई.पूरन कुमार व एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने सरकार के सामने असहज स्थिति व बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि, देर से ही सही फौरी तौर पर मामले का पटाक्षेप हुआ, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस कर कदम बढ़ाए। एडीजीपी द्वारा आत्महत्या की खबर उन्हें जापान दौरे के दौरान मिली तो उन्होंने दौरे में शामिल उनकी पत्नी अमनीत को अधिकारियों के साथ तुरंत भारत भेजा। भारत आते ही खुद भी वे सीधे एडीजीपी के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तो एएसआई संदीप लाठर के घर भी परिवार को संबल देने गए।

बहरहाल, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नायब सैनी को जरूर मिला है। कई विकास योजनाएं कायदे से सिरे चढ़ी हैं। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना ट्रंप कार्ड साबित हुई है। विधानसभा चुनावों में इस योजना के वायदे का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र चुनावों की तर्ज पर हरियाणा में भी भाजपा को खासा लाभ मिला। मिले परिणामों ने तमाम कयासों को निरर्थक साबित किया। हर जरूरतमंद महिला को सरकार की तरफ से 21 सौ रुपये मिलना, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन देना ही है। पहले चरण में बाइस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये अपनी छत का सपना पूरा करना एक दुष्कर कार्य है। हरियाणा सरकार ने दस हजार से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में गरीबों को पचास-पचास गज व छोटे गांवों में सौ-सौ गज के प्लाट उपलब्ध कराये। शहरों में ये 25 गज के रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत मिलने वाले ढाई-ढाई लाख रुपये ने उनके घर के सपने को हकीकत बनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की खासियत लोगों के साथ सहज उपलब्धता है। उनकी सुबह कबीर कुटीर में जन संवाद से शुरू होती है और रात फाइलों के साथ खत्म होती है। जनता के लिये सहज उपलब्धता और निरंतर संवाद लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त होती है। उनके चंडीगढ़ आवास में सुबह से ही मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। निस्संदेह, आम जन ही सरकार को बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, जो नौकरशाही की जटिलताओं के चलते सहज अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। बेरोजगारी की समस्या किसी भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती होती है। राज्य में चौबीस हजार बेरोजगारों को ग्रुप सी की नौकरियां देना राज्य सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा गया। वहीं लोकसेवा आयोग के माध्यम से 1311 पदों पर चयन और एचकेआरएन पोर्टल को पारदर्शी भर्ती प्रणाली के रूप में विकसित करना, राज्य सरकार की रोजगार के साथ स्थायित्व की नीति का संकेत माना जा सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि नायब सरकार आने वाले चार सालों में जनाकांक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतर पाएगी।

आत्मनिर्भरता से ही सुधरेगी देश की सेहत

> भारत ने वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 252 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को खेती में शामिल किया जाएगा, ताकि दालों के आयात पर निर्भरता घटे और देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए वर्ष 2030-31 तक उत्पादन को 252 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया है। इस हेतु 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि दलहन उत्पादन के दायरे में लाई जाएगी। विडंबना देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देश है, लेकिन दालों की आपूर्ति आयात पर निर्भर है।

आहार में पौष्टिक तत्वों का कारक मानी जाने वाली दालें, बढ़ते दामों के कारण गरीब की शारीरिक जरूरत पूरी नहीं कर रही हैं। ये हालात मानसून के दौरान औसत से कम या ज्यादा बारिश होने से तो उत्पन्न होते ही हैं, किसान के नकदी फसलों की ओर रुख करने के कारण भी हुए हैं। यही नहीं, यह स्थिति इसलिए भी बनी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान को खाद्य वस्तुओं की बजाय, ईंधन और फूलों की फसल उगाने के लिए, कृषि विभाग ने जागरूकता के अभियान चलाए। यही वजह रही कि भूमंडलीकरण के दौर में दालों की पैदावार लगातार कम होती चली गई। दाल उत्पादन का रकबा लगभग 15 हजार हेक्टेयर कम हो गया। भारत में दालों की सालाना खपत 220 से 230 लाख टन है। मांग और आपूर्ति के इस बड़े अंतर के चलते जमाखोरों और दाल के आयातक व्यापारियों को भी बार-बार करने का मौका मिल जाता है।

पौष्टिक आहार देश के हरेक नागरिक के स्वस्थ जीवन से जुड़ा अहम प्रश्न है। संविधान के मूलभूत अधिकारों में भोजन का अधिकार शामिल है। चूंकि दालें प्रोटीन और पौष्टिकता का महत्वपूर्ण

जरिया हैं, इसलिए इनके आयात होने के कारण इनके भाव भी बीच-बीच में बढ़ जाते हैं। इस कारण मध्यवर्गीय व्यक्ति की थाली से दाल गायब होने लगती है। चूंकि दाल व्यक्ति की सेहत से जुड़ी है और बीमारी की हालत में तो रोगी को केवल दाल-रोटी खाने की ही सलाह चिकित्सक देते हैं। वर्ष 1951 में प्रतिव्यक्ति दालों की उपलब्धता 60 ग्राम थी, जो वर्ष 2010 में घटकर 34 ग्राम रह गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह मात्रा 80 ग्राम होनी चाहिए। दालें भारत में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। लेकिन स्थानीय मांग पूरी करने के लिए दाल उत्पादन में किसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुअर दाल की फसल आठ माह में तैयार होती है। बावजूद किसान को उचित दाम नहीं मिलते हैं। गोया, किसान साल में एक फसल उगाने में रुचि कैसे लें? विदेशों में रहने वाले भारतीय भी सबसे ज्यादा तुअर की दाल खाना पसंद करते हैं। देश में सबसे अधिक चने और अरहर की खेती होती है। इनके अलावा मूंग और उड़द दालें पैदा होती हैं। देश में 10 राज्यों के किसान दालों की खेती करते हैं। इनमें सबसे अधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दालें मुख्य रूप से खरीफ की फसल हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इस ऋतु में करीब 70 प्रतिशत दालों का उत्पादन होता है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दालों के तात्कालिक भाव 85.42 रुपये प्रति किलो से लेकर 112.88 रुपए प्रति किलो तक हैं। भावों में इस उछाल का कारण जमाखोरी और सट्टेबाजी के साथ आयात का कुचक्र है। टाटा, महिंद्रा, ईजी-डे और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां जब से दाल के व्यापार से जुड़ी हैं, तब से ये जब चाहे तब मुनाफे के लिए दाल से खिलवाड़ करने लग जाती हैं। जब कंपनियां बड़ी तादाद में दालों का भंडारण कर लेती हैं, तो भावों में कृत्रिम उछाल आ जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दालों का भंडारण सितंबर 2024 से सीमित किया हुआ है। इस कारण भाव नियंत्रण में हैं। मीडिया दाल के बढ़ते भावों को गरीब की थाली से जोड़कर उछालता है। तब सरकार दाल के आयात के लिए विवश हो जाती है। मसलन देसी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हर हाल में पौ-बारह बने रहते हैं। इन कंपनियों का दबदबा इतना है कि कोई भी राज्य सरकार इनके गोदामों पर छापे डालने का जोखिम उठाने का साहस नहीं जुटा पाती। लिहाजा कालाबाजारी बदस्तूर रहती है। ये कंपनियां मसूर और मटर की दाल कनाडा से, उड़द और अरहर की दाल बर्मा के रंगून से, राजमा चीन से और काबुली चना ऑस्ट्रेलिया से आयात करती हैं। इनके अलावा अमेरिका, रूस, केन्या, तंजानिया, मोजांबिक, मलावी और तुर्की से भी दालें आयात की जाती हैं। कनाडा ने मसूर दाल के भाव पिछले साल की तुलना में दोगुने कर दिए हैं। कनाडा एशियाई देशों में सबसे ज्यादा दालों का निर्यात करने वाला देश है।

इस नाते यह कहने में कोई दो राय नहीं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात तो छोड़िए, देशी कंपनियां भी भारतीय कृषि को बदहाल बनाए रखना चाहती हैं। आयात की जब इन्हें खुली छूट मिल जाती है तो ये जरूरत से ज्यादा दाल व तेल का आयात करके भारत को डंपिंग ग्राउंड बना देती हैं। तय है, कालांतर में भारत की तरह दूसरे देशों में यदि मौसम रूठ जाता है तो दाल और प्याज की तरह खाद्य तेल के भाव भी आसमान छूने लगते हैं। सस्ते तेल का आयात जारी रहने की वजह से ही भारत में तिलहन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बावजूद हमारे नेता ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे रहे हैं कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भारत पूरी तरह स्वावलंबी बना रहे।

मौजूदा केंद्र सरकार ने 100 पिछड़े जिलों में दालों के उत्पादन का दायरा बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

प्रेरणा

सद्गुणों का दीप : लक्ष्मी के विचरण का रहस्य

देवलोक की प्रभा उस दिन कुछ अधिक ही उज्ज्वल थी। नंदन वन की पुष्पों से भी एक अलग आभा झर रही थी, और सुरलोक की वीणाओं में मधुर लय गूंज रही थी। तभी इंद्र सभा के द्वार पर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और उस तेज के मध्य देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। क्षणभर के लिए समस्त देवगण विस्मय में स्तब्ध रह गए। वे देवी को देखकर जैसे स्वयं में लौट आए हों। इंद्र तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, और उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर कहा — "मातः! आप तो सहस्रों युगों से असुरों के अधीन लोकों में थीं, आज यह दिव्य सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त हुआ?"

लक्ष्मी मुस्कुरा दीं। उनकी मुस्कान में सौंदर्य ही नहीं, शांति और गहराई का मिश्रण था। उन्होंने सहज स्वर में कहा — "देवराज, मैं किसी एक लोक, किसी एक गृह, या किसी एक व्यक्ति की नहीं हूं। मेरा स्वभाव ही गमनशील है। मैं वहां जाती हूं, जहां सद्गुणों का वास होता है। मैं वहां नहीं ठहरती जहां लोभ, क्रोध, अहंकार और छल का शासन है। मुझे स्थिरता नहीं, प्रवाह प्रिय है।"

सभा में क्षणिक मौन छा गया। वरुण देव आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले — "देवी, यदि यह आपका नियम है, तो कृपा कर बताएं कि किन गुणों के आधार पर आप किसी लोक में ठहरती हैं?"

देवी ने मधुर दृष्टि से सभा को निहारा। उनके मुख से जो वचन निकले, वह कालातीत सत्य बन गए। उन्होंने कहा — "जब तक किसी समाज, किसी मनुष्य या किसी लोक में संयम, सत्य, करुणा, परिश्रम, पवित्रता और मधुरता विद्यमान रहते हैं, मैं वहां निवास करती हूं। जब-जब ये गुण लुप्त होते हैं, मैं वहां से विदा ले लेती हूं। धन और वैभव तो मेरा बाह्य स्वरूप है; पर मेरा वास्तविक रूप इन सद्गुणों के भीतर बसता है।"

इंद्र ने चिंतनमग्न स्वर में पूछा — "देवी, क्या असुरों में भी कभी ये गुण रहे?" लक्ष्मी बोलीं — "हाँ देवराज, समय साक्षी है कि जब देवगण अपने गौरव में मदमत्त हो उठे थे, तब असुरों में संयम, एकता और परिश्रम का तेज था। उसी समय मैं असुरलोक में चली गई। परंतु जब वहां भी अहंकार और हिंसा ने प्रवेश किया, तो मैं उन्हें छोड़कर चल दी। आज जब मैंने देखा कि देवों में फिर से करुणा और सौम्यता का संचार हो रहा है, तो मैं पुनः यहां आ गई हूं। परंतु ध्यान रहे, यदि फिर से आपके हृदयों में लोभ या विभेद ने जन्म लिया, तो मैं पुनः प्रस्थान कर जाऊंगी।"

सभा मौन हो गई। हर देवता जैसे अपने भीतर झांकने लगा। लक्ष्मी का यह संदेश केवल देवों के लिए नहीं था — यह पूरे सृष्टि के लिए था।

देवी ने आगे कहा — "मुझे सोने के महलों, रत्नों के खजानों या फूलों की आरती से प्रसन्नता नहीं होती। यदि किसी के हृदय में सच्चा भाव, श्रम का आदर और वाणी में मधुरता है, तो मैं स्वतः वहां बस जाती हूं। मुझे आमंत्रित करने के लिए किसी शंख या दीप की आवश्यकता नहीं, केवल सत्यनिष्ठ हृदय चाहिए। मैं वहीं स्थायी होती हूं जहां मनुष्य कर्मठ है, परंतु कर्म में छल नहीं; समृद्ध है, परंतु गर्व नहीं; वाणी में तेज है, परंतु कटुता नहीं।"

इंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा — "मातः, यदि कभी हमारे भीतर पुनः दुर्बलता या अहंकार आ जाए, तो क्या हमें आपको रोकने का कोई उपाय है?" देवी ने मृदुल स्वर में उत्तर दिया — "केवल एक उपाय है — आत्मसुधार। मैं उस मनुष्य से कभी दूर नहीं जाती जो अपनी त्रुटियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। सच्ची साधना वही है जो भीतर की अशुद्धि को बुहार दे, बाहर की आरती तो केवल प्रतीक है।"

यह कहकर लक्ष्मी की दिव्य छवि जैसे स्वर्ण किरणों में विलीन होने लगी। पर उनके वचनों का कंपन अभी भी उस सभा में गूंज रहा था — "सद्गुणों में ही लक्ष्मी का वास है। जहां सद्गुण है, वहां मैं हूं; जहां पाप है, वहां मैं नहीं।"

तब वरुण देव ने इंद्र की ओर देखा और कहा — "देवराज, अब हमें अपने महलों की नहीं, अपने मनों की सफाई करनी चाहिए। दीपक बाहर भी जलाएं और भीतर भी।"

और उस दिन से यह माना गया कि दिवाली के दीप केवल रोशनी के लिए नहीं, बल्कि उन सद्गुणों के स्वागत के लिए जलाए जाते हैं जिनमें लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं — करुणा, संयम, सत्य, और प्रेम। जो इन गुणों का दीप जलाए, उसके घर से लक्ष्मी कभी विदा नहीं होती।

आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, गठबंधन सस्पेंस बरकरार! नीतीश-तेजस्वी के नाम की घोषणा का इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट के बंटवारे के बाद भले ही चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), कांग्रेस नीत इंडिया महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने अपने-अपने मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी तलक बरकरार रखा है। इससे मतदाताओं का संशय बढ़ता जा रहा है। इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिन में ही तारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन सहयोगियों ने इनके पर कतर डाले हैं! यही वजह है कि एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम अब स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। जबकि भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज की सुविचारित रणनीति है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधायक दल करेगा। सवाल है कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा? क्या नीतीश कुमार के इशारे पर उन्होंने ऐसा कहा, या फिर कोई और बात है।

बताया जाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विगत दो दशकों से इस पद पर एन-केन-प्रकारेण काबिज हैं। बीच में उन्होंने कुछ समय के लिए दलित नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया था, लेकिन उनके रंग बदलने के बाद फिर से कमान अपने हाथ में ले लिए। वर्ष 2020 के चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद भी भाजपा नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाये रखा, जिससे उनके सियासी महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार को बिहार की समाजवादी सियासत का चाणक्य तब से कहा जाता है, जबकि भाजपा के राजनीतिक चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह सिर्फ गुजरात की सियासत तक सीमित थे। ऐसे में नीतीश कुमार और उनके समर्थकों की इच्छा है कि भावी मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की जाए। जबकि भाजपा सिर्फ इतना कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही राजग चुनाव लड़ रहा है।

समझा जा रहा है कि भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हम और रालोमो के बीच टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचातानी चली, उससे एनडीए की प्रतिष्ठा और साख दोनों प्रभावित हुई है। इसलिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फूंक-फूंक कर कोई भी कदम उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि उम्रदराज नेता नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होते ही युवा वर्ग एनडीए से छिटक सकता है। दूसरा डर यह है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होते ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो सकता है। तीसरा डर यह है कि नीतीश कुमार के विरोधी भीतरघात कर सकते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार को एक मौका और दिए जाने की वकालत एनडीए में जारी है।

ठीक इसी प्रकार कांग्रेस भी इंडिया महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करने से बचना चाहती है। क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करते ही सवर्ण और दलित मतदाता कांग्रेस से छिटक जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले या बाद में इस वर्ग का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है। वहीं, अल्पसंख्यकों ने भी क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़कर कांग्रेस को प्राथमिकता दी है।

कांग्रेस पार्टी का गुप्त तौर पर यह भी मानना है कि राजद सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जंगलराज (2000-2005) को बिहार के लोग नहीं भूले हैं। ये दोनों तेजस्वी यादव के माता-पिता हैं, जिनपर कई तरह के भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। आईआरसीटीसी से जुड़े एक घोटाले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। खुद तेजस्वी यादव पर भी उपमुख्यमंत्री पद के दुरूपयोग के आरोप लगे हैं।

यही वजह है कि राहुल गांधी उनके नाम के ऐलान से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी रणनीतिकारों ने भी उन्हें यही सुझाव दिया है। इसी के चलते सीट बंटवारे में भी तेजस्वी यादव, कांग्रेस को उसका वाजिब हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जब एक कमजोर कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो 2024 के बाद मजबूत हुए कांग्रेस को 100 सीटें नहीं देना गठबंधन न्याय नहीं कहा जा सकता है।

रही बात चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की नवस्थापित पार्टी जनसुराज की तो वह शुरू से ही बिना मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा किए ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए और इंडिया महागठबंधन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं उनके उम्मीदवार एनडीए की हार की वजह बनेंगे तो कहीं इंडिया गठबंधन की हार की वजह बनेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई के बीच जनसुराज के उम्मीदवार बाजी भी मार सकते हैं। समझा जाता है कि बिहार के मतदाता टीम लालू प्रसाद और टीम नीतीश कुमार को पिछले 35 सालों से आजमा रहे हैं। इसलिए नए दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को वह ग्रेस भी दे सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिरफुटौव्वल के बिहारी मतदाता शुरू से विरोधी रहे हैं। कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, राजद, जदयू, लोजपा को सियासी सबक देने का कारण एक यह भी माना जाता है।

अभियान

धनतेरस का सच्चा रहस्य : क्या खरीदें, क्या नहीं, और क्यों

धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का अवसर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन का क्षण है। दीपावली से दो दिन पहले जब पूरे वातावरण में शुद्धि और उत्साह का संचार होता है, तब यह दिन हमें केवल वस्तुएं खरीदने नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और घर की तरंगों को शुद्ध करने का भी अवसर देता है। किंतु अनेक बार हम परंपरा की गहराई को जाने बिना ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो शुभता की जगह अशुभता को बुला लेती हैं।

कहा जाता है कि धनतेरस का उद्गम उस क्षण से जुड़ा है जब समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस क्षण में अमृत का प्रतीक था—जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु। इसीलिए यह दिन केवल "धन" का नहीं, बल्कि धन्य जीवन का पर्व है। परंतु जब मनुष्य धन के पीछे केवल भौतिक अर्थ में दौड़ने लगता है, तब वही शुभ दिन उसके लिए बाधा बन जाता है।

धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि का धातु है—शक्ति तो रखता है पर उसका स्वभाव 'रोकने' और 'भारी करने' का होता है। इस दिन यदि हम लोहे की वस्तुएं लाते हैं, तो वह शुभता की प्रवाहमान ऊर्जा को भारी बना देता है। इसलिए सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी धातुएं शुभ मानी गई हैं, क्योंकि वे सूर्य और बृहस्पति की सकारात्मक तरंगें अपने भीतर रखती हैं।

काले रंग की वस्तुएं भी इसी कारण वर्जित कही गई हैं। काला रंग ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोख लेता है, जबकि इस दिन हमें अपने घर में प्रकाश और विस्तार चाहिए। धनतेरस का पूरा भाव है प्रकाश की ओर गमन—अंधकार से नहीं, उजाले से संवाद। जो व्यक्ति इस दिन काले कपड़े या सजावटी वस्तुएं खरीदता है, वह अनजाने में उसी अंधकार को अपने घर का अतिथि बना लेता है जिससे बचना चाहिए।

पुराने सिक्के या इस्तेमाल की गई प्रतिमाएं भी अशुभ मानी जाती हैं क्योंकि उनमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा छाप होती है। हर वस्तु अपनी तरंग रखती है, और जब हम किसी दूसरे की ऊर्जा को अपने घर बुला लेते हैं, तो वह हमारे घर की समरसता को प्रभावित करती है। इसीलिए इस दिन नए सिक्के, नई लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाएं खरीदना ही वास्तविक शुभ कर्म है।

कांच की वस्तुएं भी वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कांच में स्थायित्व नहीं होता, वह नाजुक और अस्थिर होता है। जबकि लक्ष्मी का अर्थ है स्थायित्व, सौम्यता और गरिमा। इसलिए धनतेरस पर कांच के बजाय धातु की चीजें खरीदनी चाहिए — क्योंकि धातु पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जो स्थिरता और समृद्धि का मूल है।

अब बात झाड़ू की — झाड़ू धनतेरस के दिन एक विशेष प्रतीक है। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि झाड़ू से हम न केवल घर की धूल, बल्कि जीवन की नकारात्मकता को भी बुहारते हैं। परंतु इसकी खरीद का समय और स्थिति बेहद सूक्ष्म होती है। शाम के समय झाड़ू खरीदना या प्लास्टिक की झाड़ू लेना अशुभ माना गया है। कारण यह कि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की ऊर्जाएं बदलती हैं और उस समय नई वस्तुओं का ग्रहण 'स्थायी लाभ' नहीं देता। झाड़ू केवल प्राकृतिक तिनकों की बनी होनी चाहिए, क्योंकि वही धरती की सत्व-ऊर्जा को अपने में रखती है।

धनतेरस के दिन कर्ज लेकर खरीदारी करना भी निषेध बताया गया है। यह केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। जब हम ऋण लेकर उत्सव मनाते हैं, तो ब्रह्मांड में एक "ऋण-ऊर्जा" का बीज बो देते हैं। फिर वही ऊर्जा भविष्य में बार-बार कर्ज के रूप में लौटती है। इसीलिए कहा गया है — "जिसके पास जितना है, उसी में संतोष रखो, वही असली लक्ष्मी की कृपा है।"

धनतेरस का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि आप हर वस्तु खरीदें — बल्कि यह है कि जो वस्तु खरीदें, वह नए आरंभ का प्रतीक हो। सोना-चांदी इसलिए शुभ हैं क्योंकि वे सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का संगम हैं — एक गर्मी देता है, दूसरा शीतलता; एक क्रिया है, दूसरा करुणा। इन्हीं के बीच सृष्टि का संतुलन है।

आज जब हम बाजारों में चमक-दमक देखते हैं, तो भूल जाते हैं कि धनतेरस का मूल उद्देश्य भोग नहीं, योग है। जो वस्तु खरीदी जाए, उसमें श्रद्धा और शुद्धता का भाव होना चाहिए। लक्ष्मी तभी आती हैं जब मन में लोभ नहीं, विनम्रता होती है। इसलिए इस बार जब आप धनतेरस की खरीदारी करने जाएं, तो केवल बर्तन या आभूषण न देखें — अपनी नीयत भी देखें। मन साफ़ है तो कांच भी चमकेगा, मन गंदा है तो सोना भी धुंधला पड़ जाएगा।

लक्ष्मी वही आती हैं जहां भीतर प्रकाश हो, जहां कोई छिपी हुई कालिख न हो। इसलिए दीपावली से पहले घर के साथ-साथ हृदय की सफाई भी करिए। यही सच्ची धनतेरस है — जहां खरीदी गई वस्तु नहीं, बल्कि जाग्रत चेतना लक्ष्मी को आमंत्रित करती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

राज्य मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय

कैबिनेट मंत्रीः

श्री जितेन्द्रभाई सवजीभाई वाघाणी

सीट नंबर : 105, निर्वाचन क्षेत्र : भावनगर (पश्चिम) (भावनगर शहर)
जन्म : 28 जुलाई, 1970, वरतेज
व्यवसाय : कृषि और निर्माण
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 14वीं गुजरात विधानसभा के दौरान 16 सितंबर 2021 से 09 दिसंबर 2022 तक प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में सेवाएं दीं। इसके अलावा, 15वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में गुजरात विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में 20 अप्रैल 2023 से कार्यरत हैं।
शौक : पठन, समाज सेवा, लोक साहित्य, खेल और यात्रा

श्री नरेशभाई मगनभाई पटेल

सीट नंबर : 176, निर्वाचन क्षेत्र : गणदेवी (अ.ज.जा.) (जिला- नवसारी)
जन्म : 1 जून, 1969, मोगरावाड़ी, नवसारी
व्यवसाय : कृषि और व्यापार
संसदीय करियर : 12वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 14वीं गुजरात विधानसभा में आदिजाति विकास और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राहक सुरक्षा विभाग के मंत्री के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन, लेखन, संगीत और क्रिकेट

श्री अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिया

सीट नंबर : 83, निर्वाचन क्षेत्र : पोरबंदर (जिला- पोरबंदर)
जन्म : 17 फरवरी, 1957, मोढवाडा, पोरबंदर
व्यवसाय : सामाजिक गतिविधियां और कृषि
संसदीय करियर : 11वीं और 12वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, उन्होंने अगस्त-सितंबर, 2003 के दौरान श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के एशिया क्षेत्र की दूसरी कॉन्फ्रेंस में गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया।
शौक : पठन, टेनिस, वृक्षारोपण, युवा गतिविधियां और व्यसन निर्मूलन

डॉ. प्रद्युमन गनुभाई वाजा

सीट नंबर : 92, निर्वाचन क्षेत्र : कोडिनार (अ.जा.) (जिला- गिर-सोमनाथ)
जन्म : 18 अगस्त, 1969, कुतियाणा
व्यवसाय : डॉक्टर
संसदीय करियर : 12वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।
गतिविधियां : ट्रस्टी, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन
शौक : पठन, यात्रा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां

श्री रमणभाई भीखाभाई सोलंकी

सीट नंबर : 109, निर्वाचन क्षेत्र : बोरसद (जिला- आणंद)
जन्म : 28 अप्रैल, 1965, वटादरा, तहसील-खंभात
व्यवसाय : सेवानिवृत्त शिक्षक, कृषि
संसदीय करियर : 15वीं गुजरात विधानसभा में उप मुख्य सचेतक के रूप में 12 दिसंबर, 2022 से कार्यरत रहे
गतिविधियां : वर्ष 2005 से 2010 के दौरान जिला पंचायत में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, ठाकोर समाज के मंत्री के रूप में भी सेवाएं दीं।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) :

श्री ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल

सीट नंबर : 154, निर्वाचन क्षेत्र : अंकलेश्वर (जिला- भरूच)
जन्म : 25 जून, 1965, मु.पो. कुडादरा, तहसील- हांसोट, भरूच
व्यवसाय : कृषि
संसदीय करियर : 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। वे सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग में 2 मार्च, 2009 से 1 फरवरी, 2011 के दौरान संसदीय सचिव रहे। इसके अलावा, उन्होंने 2 फरवरी, 2011 से 25 दिसंबर, 2012 के दौरान सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। उन्होंने 7 अगस्त, 2016 से 25 दिसंबर, 2017 के दौरान सहकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला है तथा दिसंबर, 2017 से सितंबर, 2021 के दौरान सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग का स्वतंत्र प्रभार और परिवहन विभाग के राज्य मंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला। उन्होंने विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति, पंचायती राज समिति और आश्वासन समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
शौक : पठन, व्यायाम, यात्रा, खेल, समाज सेवा और वृक्षारोपण

डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील

सीट नंबर : 141, निर्वाचन क्षेत्र : वडोदरा (अ.जा.) (वडोदरा शहर)
जन्म : 25 मार्च, 1975, वडोदरा
व्यवसाय : सुपरवाइजर और शिक्षक, ब्राइट डे स्कूल
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने सितंबर-2021 से दिसंबर-2022 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं।
शौक : पठन

श्रीमती रीवाबा रवीन्द्रसिंह जाडेजा

सीट नंबर : 78, निर्वाचन क्षेत्र : जामनगर (उत्तर) (जामनगर जिला)
जन्म : 5 सितंबर, 1990, राजकोट
व्यवसाय : समाज सेवा
गतिविधियां : संस्थापक व मैनेजिंग ट्रस्टी, मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। कन्या केळवणी, महिला सशक्तिकरण आदि से जुड़ी गतिविधियां तथा तत्संबंधी केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज तक पहुँचाने के कार्य से जुड़ी हुई हैं।
शौक : पठन, यात्रा-पर्यटन तथा समाज सेवा

राज्य मंत्री :

श्री कांतिलाल शिवलाल अमृतिया

सीट नंबर : 65, निर्वाचन क्षेत्र : मोरबी (जिला- मोरबी)
जन्म : 8 मार्च, 1962, जेतपुर, तहसील और जिला- मोरबी
व्यवसाय : कृषि, उद्योग और शिक्षा
संसदीय करियर : 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।
शौक : पठन, समाज सेवा, यात्रा, खेल, क्रिकेट, टेनिस और तैराकी

श्री रमेशभाई भूराभाई कटारा

सीट नंबर : 129, निर्वाचन क्षेत्र : फतेपुरा (अ.ज.जा.) (जिला- दाहोद)
जन्म : 4 मई, 1975, हिंगला
व्यवसाय : कृषि
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, उन्होंने सितंबर-2021 से दिसंबर-2022 के दौरान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
गतिविधियां : सदस्य, जिला पंचायत-दाहोद
शौक : पठन और समाज सेवा

श्रीमती दर्शनाबेन मुकेशभाई वाघेला

सीट नंबर : 56, निर्वाचन क्षेत्र : असारवा विधानसभा (अहमदाबाद शहर)
जन्म : 5 सितंबर, 1972, अहमदाबाद
व्यवसाय : पूर्व शाला आचार्य
गतिविधियां : अहमदाबाद महानगर पालिका में दो कार्यकाल तक पार्षद रहीं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2010 से 2013 के दौरान अहमदाबाद महानगर पालिका में उप महापौर के रूप में सेवाएं दी हैं। वे सफाई कामदार निगम की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और हाल में वाल्मीकि फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं।
शौक : पठन, वक्तव्य

श्री कौशिकभाई कांतिभाई वेकरिया

सीट नंबर : 95, निर्वाचन क्षेत्र : अमरेली विधानसभा (जिला- अमरेली)
जन्म : 9 जून 1986, मोजे खीचा, तहसील धारी, जि. अमरेली
व्यवसाय : कृषि, व्यवसाय (श्री द्रोणेश्वर पेट्रोलियम)
संसदीय कॅरियर : 15वीं गुजरात विधानसभा में मुख्य उप सचेतक के रूप में दि. 12 दिसंबर 2022 से कार्यरत थे।
गतिविधियां : निदेशक, गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड, दि. 29/03/2016 से कार्यरत। पूर्व निदेशक, खेतीबाड़ी उत्पाद बाजार समिति, अमरेली
शौक : राजपुरुषों की जीवनगाथा तथा विश्व के राजनीतिक इतिहास का पठन, सामाजिक गतिविधियां, जनसंपर्क, यात्रा-पर्यटन, सिंह दर्शन

श्री प्रवीणकुमार गोरधनजी माली

सीट नंबर : 13, निर्वाचन क्षेत्र : डीसा (जिला- बनासकांठा)
जन्म : 8 मार्च 1985, डीसा
व्यवसाय : कृषि एवं व्यापार
गतिविधियां : संयोजक, प्रदेश भाजपा प्रलेखन विभाग। ट्रस्टी, महात्मा ज्योतिबा फुले एजुकेशन ट्रस्ट, डीसा
शौक : पठन, साइकलिंग, वॉलीबॉल

डॉ. जयरामभाई चेमाभाई गामित

सीट नंबर : 172, निर्वाचन क्षेत्र : नीझर (अजजा) (जिला- तापी)
जन्म : 1 जून 1975, कटारावाण, तहसील- उच्छल (तापी)
व्यवसाय : कृषि एवं पशुपालन
गतिविधियां : अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, तापी जिला
शौक : लेखन, पठन, सांस्कृतिक कार्यक्रम

श्री त्रिकमभाई बीजलभाई छांगा

सीट नंबर : 4, निर्वाचन क्षेत्र : अंजार (जिला- कच्छ)
जन्म : 1 जून, 1962, रतनाल, अंजार, कच्छ
व्यवसाय : सेवानिवृत्त आचार्य
गतिविधियां : वर्ष 2000 से 2010 तक अंजार तहसील पंचायत के सदस्य के रूप में सेवाएं दीं और फिर 2010 से 2015 तक कच्छ जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन

श्री कमलेशभाई रमेशभाई पटेल

सीट नंबर : 113, निर्वाचन क्षेत्र : पेटलाद (जिला- आणंद)
जन्म : 12 अप्रैल 1970, संतोकपुरा, बोरसद
व्यवसाय : कृषि एवं नौकरी (आचार्य, शाहपुर हाईस्कूल)
गतिविधियां : उन्होंने पेटलाद तहसील भाजपा अध्यक्ष, चौद गाम केळवणी उत्तेजक ट्रस्ट के सचिव तथा पेटलाद एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन एवं समाज सेवा

श्री संजयसिंह विजयसिंह महिडा

सीट नंबर : 118, निर्वाचन क्षेत्र : महुधा (जिला- खेड़ा)
जन्म : 20 अक्टूबर 1979, त्राणजा, मातर
व्यवसाय : कृषि एवं व्यापार
गतिविधियां : अध्यक्ष, नडियाद तहसील पंचायत। पूर्व अध्यक्ष-कारोबारी समिति-तहसील पंचायत, तहसील संगठन महासचिव (2020 तक), सचिव-महिडा मेलड़ी माताजी मंदिर सेवा समाज ट्रस्ट, पूर्व कोषाध्यक्ष-जिला युवा मोर्चा, शिवाजी फाउंडेशन में सेवा गतिविधियों में सक्रिय।
शौक : पठन तथा संगीत

श्री पूनमचंद धनाभाई बरंडा

सीट नंबर : 30, निर्वाचन क्षेत्र : भिलोडा (अ.ज.जा.) (जिला- अरवल्ली)
जन्म : 1 जून, 1959, वांकाटिंबा
व्यवसाय : कृषि
गतिविधियां : प्रदेश भाजपा आदिजाति मोर्चे के महासचिव के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन तथा खेल

श्री स्वरूपजी सरदारजी ठाकोर

सीट नंबर : 7, निर्वाचन क्षेत्र : वाव (जिला- बनासकांठा)
जन्म : 1 जून, 1979, बैयक
व्यवसाय : कृषि, व्यापार
गतिविधियां : उपाध्यक्ष, गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना
शौक : पठन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में शामिल उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा नवनियुक्त मंत्रियों में 5 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 12 राज्य मंत्री शामिल

▸▸ राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने महात्मा मंदिर में आयोजित गौरवशाली समारोह में मंत्रियों को दिलाई शपथ

▸▸ कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री कुंवरजीभाई बावळिया तथा राज्य मंत्री श्री परषोत्तमभाई सोलंकी को वर्तमान मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में नए शामिल किए गए उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के समक्ष उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री हर्ष संघवी तथा राज्य मंत्रिपरिषद के 5 कैबिनेट मंत्रियों, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 12 मनोनीत राज्य मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली।

कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री जितेन्द्रभाई वाघाणी, श्री नरेशभाई पटेल, श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युम्नभाई वाजा और श्री रमणभाई सोलंकी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में श्री ईश्वरसिंह पटेल, श्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया और श्रीमती मनीषा वकील ने शपथ ग्रहण की।

वहीं, राज्य मंत्री के रूप में श्री कांतिलाल अमृतिया, श्री रमेशभाई कटारा, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, श्री कौशिकभाई वेकरिया, श्री प्रवीणकुमार माळी, डॉ. जयरामभाई गामित, श्री त्रिकमभाई छांगा, श्री कमलेशभाई पटेल, श्री संजयसिंह महीड़ा, श्री पी.सी. बरंडा, श्री स्वरूपजी ठाकोर और श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने राज्यपाल के समक्ष शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों सर्वश्री कनुभाई देसाई, ऋषिकेशभाई पटेल और कुंवरजीभाई बावळिया तथा राज्य मंत्री श्री परषोत्तमभाई सोलंकी को इस नई मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया है।

इस शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री मनसुख मांडविया, सी.आर. पाटिल, सांसद एवं विधायक, संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ अग्रणी, साधु-संतों और समाज के विभिन्न वर्गों के अग्रणियों सहित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं विशाल संख्या में शुभचिंतक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया।

ऑपरेशन जीवन रक्षा

अपनी जान जोखिम में डालकर कांस्टेबल श्री रमेश जाधवने बचाई एक बच्चे की जान

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के गोधरा के रेल सुरक्षा बल में कार्यरत कांस्टेबल श्री रमेश जाधव ने अत्यंत साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर असावधानीवश ट्रेन से गिरे एक 3 वर्षीय बालक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 16.10.2025 को ट्रेन नं 19038 बरौनी - बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस के कोच सं S5 में श्री संतोष यादव अपनी पत्नी एवं 03 वर्षीय पुत्र के साथ मुजफ्फरपुर से वापी यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान कानसुधी–गोधरा रेलखंड पर, ट्रेन के गोधरा यार्ड में प्रवेश से पहले, बालक अपनी माता के साथ शौचालय जाते समय असावधानीवश दरवाजे के पास से फिसलकर दूसरी रेल लाइन पर नीचे गिर गया।

बालक के गिरते ही यात्रियों द्वारा तत्काल चेन खींचकर ट्रेन रोकी गई। उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात गोधरा में कार्यरत कांस्टेबल श्री रमेश जाधव ने घटना स्थल पर बालक को देखा। उसी समय उस रेल लाइन पर ट्रेन नं 12951 मुंबई - नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री रमेश जाधव ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अत्यंत साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए तेज गति से लाइन पर दौड़ लगाई और आने वाली ट्रेन के पहले बालक तक पहुँचकर उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया।

श्री रमेश जाधव ने बालक की तत्परता से जान बचाने के बाद उसे उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया। यात्री ने अपने पुत्र के शरीर पर कोई चोट ना आने की पुष्टि की तथा अपनी यात्रा जारी रखी। घटना के पश्चात कोच में उपस्थित सभी यात्रियों एवं परिजनोंने कांस्टेबल श्री रमेश जाधव के साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

गुजरात से औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप कश्मीर पहुँची

(जीएनएस)। कश्मीर घाटी में माल परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। 1,350 टन औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप गुजरात के अहमदाबाद मंडल के खाराघोड़ा (KOD) स्टेशन से जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग (ANT) स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुँची है।

स्थानः खाराघोड़ा गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध नमक उत्पादन क्षेत्र है, जो लिटिल रण ऑफ कच्छ की सीमा पर बसा हुआ है।

शुद्धताः खाराघोड़ा का नमक अपनी उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्पादित कुछ प्रकार के नमक में 98% से अधिक सोडियम क्लोराइड (NaCl) होता है। इस क्षेत्र की रिफ़ाइनरियाँ औद्योगिक और खाद्य दोनों श्रेणियों का नमक तैयार करती हैं।

प्रयोगः इस खेप का उपयोग चमड़ा उद्योग, साबुन निर्माण तथा ईंट भट्ठों में किया जाएगा।

यह उपलब्धि कश्मीर में रेल नेटवर्क के माध्यम से गैर-पारंपरिक माल ढुलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे परिवहन समय और लागत में कमी आने के साथ-साथ सड़क परिवहन पर निर्भरता भी घटेगी।

यह रेल रेक लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर खाराघोड़ा से अनंतनाग पहुँची।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा,यात्रियों से जुड़ने के लिए "अमृत संवाद" का आयोजन बदलाव के लिए बातचीत, सेवा के लिए प्रतिबद्धता - जन संवाद से जन विकास

(जीएनएस)। पहली तस्वीर में मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर अमृत संवाद के दौरान यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अमृत काल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त पंच प्राण के मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित होकर पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन के कॉनकोर्स एरिया में एक गतिशील "अमृत संवाद" का आयोजन किया गया। विशेष अभियान 5.0 के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे अधिकारियों और यात्रियों के बीच सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देना था।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने किया, जिन्होंने अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ एक खुले प्रश्नोत्तर सत्र में यात्रियों से सीधे बातचीत की। इस संवाद में यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जन सुरक्षा, स्टेशन सुविधाओं, डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ प्रीमियम स्लीपर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछे और सुझाव साझा किए।

मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक उत्तर दिया और यात्रियों को यात्री सुविधाओं में वृद्धि, सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने और आधुनिक, तकनीक-संचालित यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासों का आश्वासन दिया। उन्होंने यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने, ज़िम्मेदार यात्रा आदतें अपनाने और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सकारात्मक योगदान देकर रेलवे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

अमृत संवाद पहल का उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच सहभागिता को सशक्त बनाते हुए ऐसा संवाद मंच तैयार करना है, जहां जनसुझावों को ठोस नीतिगत एवं विकासात्मक कार्यों में रूपांतरित किया जा सके। यह पहल अमृत काल और पंच प्राण के संकल्पों से प्रेरित होकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड में 120 किमी की स्पीड से ट्रेन का हुआ संचालन,42 किमी की दूरी 25 मिनट में की पूरी, औसत गति 101 किमी से अधिक की आई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण रेलवे संरक्षा आयुक्त (CRS), वेस्टर्न सर्कल श्री ई. श्रीनिवास द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर, 2025 को किया गया। अंतिम संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। इस रेलखंड को मई 2022 में 415.37 करोड़ की लागत से मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब यह खंड यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुचारू रेल संचालन हेतु लगभग तैयार है। रेल सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम सर्कल) द्वारा किया गया वैधानिक निरीक्षण कमीशनिंग से पहले एक आवश्यक कदम है। निरीक्षण टीम ने स्टेशन सुविधाओं, ट्रैक ज्योमेट्री, घुमाव, पुलों और रोड अंडर ब्रिज (RUBs) की विस्तृत जांच की। इसमें 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज और 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) शामिल हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है, तथा इस खंड पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं। 17 अक्टूबर, 2025 को विभिन्न स्थानों पर विस्तृत निरीक्षण किया गया। कुकरवाडा से वीजापुर तक लगभग 15 किमी का ट्रॉली निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड (42.32 किमी) पर 120 किमी/घंटे की स्पीड से गति परीक्षण किया गया। इस दौरान श्री ई. श्रीनिवास, रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे, श्री वेद प्रकाश मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद; श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कुकरवाडा स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊँचाई, कॉपिंग और एंड पाथवे की जांच की गई। RUB संख्या 65 B में ऊँचाई, गेज और जल निकासी की व्यवस्था देखी गई, साथ ही MDD (Maximum Dry Density) टेस्ट, बैंक स्लोप और सेस की चौड़ाई की भी जांच की गई।

इसी प्रकार, गेरिता–कोलवाड़ा में प्लेटफार्म की माप और एंड पाथवे की जाँच की गई। RUB संख्या 79B की ऊँचाई, गेज, जल निकासी और पैदल मार्ग की व्यवस्था देखी गई। विजापुर स्टेशन पर ट्रैक के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत निरीक्षण किया गया। प्लेटफार्म की कॉपिंग, ऊँचाई एंड पाथवे की जांच की गई। विजापुर स्टेशन में सबवे का निरीक्षण किया गया, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं की भी जाँच की गई।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से यात्रियों और क्षेत्र को कई लाभ प्राप्त होंगे। मालगाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित होगा और इस खंड के चालू होने से विजापुर क्षेत्र से कॉटन, गेहूँ, आलू एवं टोबेको, तेल उत्पाद इत्यादि की आपूर्ति देशभर में अधिक सुगमता से हो सकेगी, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी। अभी तक सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता था, वह अब रेल मार्ग से शीघ्र भेजा जा सकेगा। इससे स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा तथा रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। यात्रियों को बेहतर और तेज़ रेल संपर्क उपलब्ध होगा, विशेष रूप से उत्तर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत संरचनाओं और आधुनिक सुरक्षा उपायों के साथ यात्रा अब अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

“स्वच्छता पखवाड़ा – 2025” के अंतर्गत भावनगर मंडल में विविध कार्यक्रमों का सफल आयोजन

(जीएनएस)।पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल पर “स्वच्छता पखवाड़ा – 2025” के अंतर्गत विभिन्न स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का शुभारंभ 01 अक्टूबर 2025 को प्रभात फेरी एवं स्वच्छता शपथ के साथ हुआ। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में रेलकर्मी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं वरिष्ठ मंडल याँत्रिक इन्जीनियर श्री संतोष कुमार मिश्रा की देखरेख में चलाए गए अभियान के दौरान प्रत्येक दिन को एक विशिष्ट थीम के अंतर्गत मनाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से — स्वच्छता शपथ दिवस, स्वच्छता जागरूकता दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ ट्रैक, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ कार्यस्थल, स्वच्छ आवासीय परिसर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ पानी, स्वच्छ प्रसाधन, सिंगल यूज प्लास्टिक निषेध एवं स्वच्छता रैली शामिल थे।

महात्मा गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस (02 अक्टूबर 2025) के अवसर पर वृक्षारोपण, निरीक्षण एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने विभिन्न स्थलों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही, चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता 12 बच्चों एवं स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। “स्वच्छ रेलगाड़ी” थीम के अंतर्गत पोरबंदर, भावनगर एवं वेरावल कोचिंग डिपो में ट्रेनों की गहन यांत्रिक सफाई की गई। साथ ही, स्टेशनों पर यात्रियों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। “स्वच्छ आहार” दिवस के अवसर पर मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा भावनगर टर्मिनस, जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर, जेतलसर, बोटाद, सोनगढ़, धोला एवं धोलका स्टेशनों पर खाद्य स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। पेंट्री कार विक्रेताओं एवं स्टॉल संचालकों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छ आहार के महत्व से अवगत कराया गया।

अभियान के दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर गहन सफाई अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं एवं कार्यालयों की संपूर्ण सफाई कर कर्मचारियों एवं यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। “स्वच्छ पटरी” कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों द्वारा रेलवे ट्रैकों की सफाई की गई।

इसके अतिरिक्त, “वेस्ट टू आर्ट”, श्रमदान, रैलियों एवं वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के माध्यम से रेलकर्मियों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। यात्रियों से स्वच्छता के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा भविष्य की योजनाओं हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 17 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिती में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और “स्वच्छता पखवाड़ा – 2025” अभियान के अंतर्गत किये गये क्रियाकलापों की जानकारी दी एवं कहा कि भावनगर मंडल ने इस पखवाड़े को जन-अभियान का स्वरूप देते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया की 1 से 15 अक्टूबर तक चले इस अभियान के दौरान हमारे मंडल के 66 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया। लगभग 925 कर्मचारियों और नागरिकों ने स्वच्छता शपथ ली और 12400 वर्गमीटर क्षेत्र की सफाई की गई। 160 मीटर नालियों की सफाई, 9 स्थानों पर फ्यूमीगेशन, और 9 एंटी-लिटरिंग ड्राइव्स के माध्यम से हमने स्वच्छता को जन-जागरूकता से जोड़ा। “स्वच्छ परिसर” के तहत 39 कार्यालयों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण किया गया, जबकि 36 किलोमीटर ट्रैक की सफाई और 2.3 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण हुआ। “स्वच्छ नीर” अभियान में 15 जलस्थलों और 10 पानी के बूथों की सफाई एवं जल गुणवत्ता की जांच की गई। भावनगर मंडल के सभी स्टेशनों पर अब साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म, सुधरी हुई जल व शौचालय सुविधाएँ, और स्वच्छ वातावरण यात्रियों को एक नया अनुभव दे रहे हैं। भावनगर मंडल ने इस अवसर पर यह संकल्प लिया कि “स्वच्छता ही सेवा” के आदर्शों को आत्मसात करते हुए रेलवे परिसरों को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपने प्रयास निरंतर जारी रखेगा।

महागठबंधन में दोस्ताना जंग: कांग्रेस और वाम दल की सीटों पर सीधी टक्कर

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने चरम पर पहुँच चुका है और इस बार चुनावी रण केवल विपक्षी दलों के बीच नहीं, बल्कि महागठबंधन के अंदर ही गर्मा गया है। गठबंधन के भीतर कई सीटों पर कांग्रेस और वाम दल आमने-सामने हैं, जिससे चुनावी रणनीति और एकता दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह ‘दोस्ताना संघर्ष’ नाम दिया गया है ताकि बाहरी तौर पर गठबंधन की एकता बनी रहे, लेकिन अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ती दिख रही है।

बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट इस समय चर्चाओं का केंद्र है। यहां कांग्रेस ने यूथ प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने पहले ही अवधेश राय को मैदान में उतार दिया था। दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर तय मानी जा रही है, और यह सीट महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान का प्रतीक बन चुकी है। लालगंज विधानसभा सीट पर भी दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। पहले यहां राजद की ओर से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के नाम पर चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट बनिया समाज से आने वाले आदित्य कुमार राजा को दिया। शिवानी शुक्ला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पैसा लेकर टिकट बेचा, हालांकि बाद में यह विवाद सुलझा लिया गया।

वैशाली और झंझारपुर विधानसभा सीटों पर भी महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। वैशाली में कांग्रेस ने संजीव कुमार को टिकट दिया, जबकि राजद ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा। झंझारपुर में वाम दल और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे पर मतभेद अब तक कायम हैं। यह स्थिति गठबंधन की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़ा करती है और चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है।

घोसी विधानसभा सीट से सीपीआई (एमएल) ने रामबली यादव को टिकट दिया है, वहीं राजद ने जदयू से आए राहुल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बायसी, बहादुरगंज, रानीगंज और सहरसा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच टकराव जारी है। वाम दलों ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को अधिक सीटें देने पर आपत्ति जताई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महागठबंधन इन दोस्ताना संघर्षों को समय रहते नहीं सुलझा पाता, तो यह केवल सीटों की टक्कर नहीं बल्कि गठबंधन में गहरी दरारों में बदल सकती है। चुनाव से पहले ही गठबंधन के अंदरूनी तनाव ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है और अब देखना यह है कि क्या महागठबंधन अपनी एकता बनाए रख पाएगा या चुनाव के रण में यह दोस्ताना जंग व्यापक संघर्ष का रूप ले लेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा ऊर्जा संरक्षण के बेहतर उपायों की पहल

(जीएनएस)। आज के दौर में जहाँ ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, रेलवे द्वारा अपने नेटवर्क में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के बिजली विभाग द्वारा बिजली की खपत कम करने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से ऊर्जा-बचत पहल शुरू की गई है। ये प्रयास एक हरित भविष्य के निर्माण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा कई प्रभावशाली ऊर्जा संरक्षण अभियान शुरू किए गए हैं। ये प्रयास भारतीय रेल की पर्यावरण संरक्षण और परिचालन दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। इस पहल के अंतर्गत, मुंबई सेंट्रल मंडल के स्टेशनों और सेवा भवनों पर लगभग 12,500 ऊर्जा-कुशल ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (BLDC) पंखे लगाए गए हैं। बीएलडीसी पंखे पारंपरिक सीलिंग पंखों की अपेक्षा लगभग 40% कम बिजली का उपयोग करते हैं, साथ ही ये अधिक शांत, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले होते हैं। इसके अलावा, मंडल द्वारा स्टेशनों, कार्यालयों और सेवा क्षेत्रों में 1,48,700 से अधिक एलईडी फिक्स्चर लगाकर ऊर्जा-कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हासिल किया गया है। इस पहल से बिजली की खपत और रखरखाव की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता बनाए रखने के लिए, दादर, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, भायंदर, सूरत, उधना, नंदुरबार और वापी सहित प्रमुख स्टेशनों पर 10 प्राकृतिक वाटर कूलर लगाए गए हैं। ये कूलर बिना कंप्रेसर के काम करते हैं और इनकी शीतलन क्षमता 45 लीटर प्रति घंटा है। ये 150 लीटर तक पानी संग्रहित कर सकते हैं। ये कूलर न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हुए 23C से 27C के बीच तापमान बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई सेंट्रल मंडल में एयर-कंडीशनिंग सिस्टम को और अधिक कुशलता से अनुकूलित करने के लिए 1,200 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी सेंसर लगाए गए हैं। ये स्मार्ट सेंसर मानवीय उपस्थिति का पता लगाते हैं और स्वचालित रूप से एयर-कंडीशनिंग को समायोजित करते हैं, जिससे खाली कमरों में अनावश्यक ऊर्जा की खपत कम होती है। इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से, पश्चिम रेलवे नवीन और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एक मजबूत उदाहरण स्थापित कर रही है, जो एक हरित और अधिक ऊर्जा-कुशल भविष्य के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

अमित शाह का RJD पर हमला: ‘जंगल राज’ ने बिहार को आधी सदी पीछे धकेला

(जीएनएस)। पटना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला किया है। उन्होंने दिवंगत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने को लेकर महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार को सुरक्षित रखने के लिए मोदी-नीतीश की जोड़ी को फिर से सत्ता में लाना होगा।

शनिवार को सारण में आयोजित जनसभा में शाह ने कहा कि उन्होंने राजद-राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की सूची देखी, जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर बिहार सुरक्षित रह सकता है।

अमित शाह ने राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू-राबड़ी के 15 साल के ‘जंगल राज’ ने बिहार को लगभग आधी सदी पीछे धकेल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दौरान बिहार ने अपनी गरिमा, वैभव और उत्कृष्टता खो दी। शाह ने कहा, “वही ‘जंगल राज’ आज बिहार की जनता के सामने नए चेहरों के साथ है और वोट मांग रहा है। उस 15 साल के दौर में बिहार ने अपने गौरव, धन और ज्ञान खो दिए। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग लालू यादव के शासन के कारण राज्य छोड़ने लगे।”

केंद्रीय मंत्री ने बिहार में उद्योग और सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि जब लालू यादव भ्रष्टाचार के मामलों में जेल से बाहर आए और हाथी पर जुलूस निकाला, तो यह राज्य की बेशर्मी और कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि उस 15 साल के शासन ने बिहार की प्रतिष्ठा और आर्थिक संभावनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया।

शाह ने महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव सुरक्षा अब बेहतर हुई है। पहले छह चरणों में चुनाव आयोजित करना पड़ता था क्योंकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं हो पा रहे थे, जबकि इस बार सिर्फ दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं क्योंकि बिहार सुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा, “आज बिहार के लोग जानते हैं कि सुरक्षित और विकासशील राज्य की जरूरत है, और इसके लिए मोदी-नीतीश की जोड़ी को फिर से सत्ता में लाना होगा।”

अहमदाबाद मंडल ने फेस्टिवल सीजन के दौरान व्यापक भीड़ प्रबंधन हेतु उठाये अहम कदम

- यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा
- सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद मंडल ने की व्यापक तैयारी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा आगामी दीवाली एवं छठ पूजा त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक भीड़ प्रबंधन एवं यात्री सुविधा उपाय किए गए हैं। इसके अंतर्गत अहमदाबाद, असारवा, साबरमती एवं गांधीधाम स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अहमदाबाद, असारवा और साबरमती स्टेशनों पर राउंड-द-क्लॉक (24x7) अधिकारियों की निगरानी में व्यापक प्रबंध किए गए है ताकि प्रत्येक स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। अहमदाबाद स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु सरसपुर साइड 3230 वर्ग फूट तथा प्लेटफॉर्म नं. 01 की ओर 8072 वर्ग फूट के यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, प्रकाश, पंखे, शौचालय एवं सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

साबरमती स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में टिकट काउंटर और 4-5 हजार यात्रियों के बैठने की सुविधा की गई है। प्रवेश एवं निकास द्वारों को पृथक रखा गया है ताकि यातायात प्रवाह सुचारू रहे। इसके अतिरिक्त, 15 से 28 अक्टूबर 2025 तक मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है, जिससे किसी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो सके।

भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुविधा देने हेतु अतिरिक्त टिकट बुकिंग काउंटर शुरू किए गए हैं। कतार नियमन, यात्री सहायता एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारी एवं RPF कर्मी भी लगाए गए हैं। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए स्टेशनों पर कवर्ड होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिससे ट्रेन के प्रस्थान तक यात्री आराम से प्रतीक्षा कर सकें।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ड्यूटी के दौरान वॉकी-टॉकी एवं बॉडी-वॉर्न कैमरा का उपयोग कर निर्बाध डिजिटल संचार बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अहमदाबाद मंडल कार्यालय में ‘वार रूम’ (War Room) स्थापित किया गया है, जहां से वास्तविक समय पर सभी स्टेशनों से समन्वय करते हुए स्थितियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यात्रियों के लाभ हेतु ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि त्योहारी सीजन में भी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध बनी रहे। इन उपायों से यात्रियों को लंबी कतारों, अनावश्यक भीड़भाड़ और असुविधा से राहत मिलेगी, साथ ही स्टेशन परिसर में सुरक्षा और स्वच्छता का स्तर भी बेहतर रहेगा। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करें और सुरक्षा कर्मियों एवं रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव सुखद और सुरक्षित बन सके।

राजस्थान में व्यवसायी की हत्या: पश्चिम बंगाल से तीन शूटर गिरफ्तार

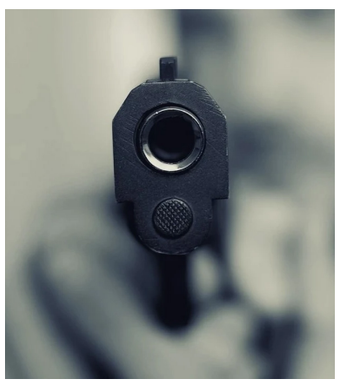

(जीएनएस)। जयपुर। राजस्थान के कुचामन सिटी कस्बे में हुए व्यवसायी की हत्या के मामले में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पश्चिम बंगाल से तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, जबकि चौथा आरोपी जुबैर अहमद अब भी फरार है। इन आरोपियों पर चार अक्टूबर को कुचामन स्थित एक जिम में व्यवसायी रमेश रुलानिया की हत्या का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद चारों आरोपी आठ दिनों तक फरार रहे और लगातार अपने ठिकानों को बदलते रहे। उन्होंने इस दौरान एक दर्जन से अधिक शहरों में लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल किया और रात में कहीं रुके बिना लगातार यात्रा की, ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। कुछ आरोपी आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर भी गए और पहचान बदलने के लिए सिर मुंडवा लिया। इसके बाद समूह अलग हो गया और जुबैर अहमद अन्य आरोपियों से अलग हो गया। तीन शूटर झारखंड होते हुए कोलकाता पहुंचे, जहां राजस्थान पुलिस की टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर उनकी लोकेशन पता की। कोलकाता पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अब उनसे पूछताछ की जाएगी और हत्या की साजिश से जुड़े अहम तथ्य उजागर होने की संभावना है।

प्रारंभ में चारों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) दिनेश एम.एन. ने गणपत, धर्मेंद्र और महेश पर इनाम बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया। पुलिस की यह कार्रवाई राजस्थान में बढ़ती हुई संगठित अपराध की चुनौती के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर नए नियम लागू किए, कोई भी संगठन बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं चला सकेगा

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को राज्य के सार्वजनिक स्थलों और सरकारी परिसरों के उपयोग को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नए निर्णय पर विस्तार से जानकारी दी और स्पष्ट किया कि यह नियम किसी विशेष संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी संगठन या समूह को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम, रैली या मार्च आयोजित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम केवल आरएसएस के लिए नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के लिए समान रूप से लागू होगा। सिद्धरमैया ने बताया कि इस फैसले की जड़ें साल 2013 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र में हैं। उस समय के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने स्कूल परिसरों और उनके जुड़े खेल के मैदानों का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए करने का निर्देश जारी किया था। नए नियम का उद्देश्य यही है कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और उनका उपयोग सुव्यवस्थित तरीके से हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियम के पालन में कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। कई संगठन पहले ही इस कदम को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों की योजना प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नियम सभी संगठनों के लिए समान रूप से लागू होंगे और किसी विशेष संगठन को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और उसकी व्यवस्थित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय कर्नाटक में राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक आयोजनों पर नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नियम का उद्देश्य केवल अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया का सम्मान करें और नियमों का पालन करके अपने कार्यक्रम आयोजित करें। इस प्रकार कर्नाटक सरकार ने राज्य में सार्वजनिक और सरकारी परिसरों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगे और राज्य की संपत्तियों के संरक्षण में सहायक होंगे।

आंध्र और कर्नाटक के आईटी मंत्रियों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग, निवेश को लेकर बढ़ा राजनीतिक तापमान

(जीएनएस)। अमरावती। दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों — आंध्र प्रदेश और कर्नाटक — के बीच एक बार फिर डिजिटल मैदान में राजनीतिक तकरार छिड़ गई है। इस बार बहस का केंद्र बना है निवेश, आईटी सेक्टर और राज्यों की आर्थिक स्थिति। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश और कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, जिसने दोनों राज्यों के समर्थकों को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है।

दरअसल, आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने हाल ही में एक्स पर लिखा— “कहते हैं आंध्र का खाना मसालेदार होता है, लगता है हमारे निवेश भी वैसे ही हैं। कुछ पड़ोसी पहले से ही इसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं।” इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लोकेश ने यह दावा भी किया कि भारत के सबसे युवा राज्य आंध्र प्रदेश को हाल के वर्षों में सबसे अधिक विदेशी निवेश मिला है। उन्होंने विशाखापत्तनम में गूगल के 15 अरब डॉलर के एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सौदा हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ और यह आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। लोकेश के इस बयान पर कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने लिखा— “निवेश केवल घोषणाओं से नहीं आते, बल्कि बुनियादी ढांचे, नीति और भरोसे से आते हैं। कुछ लोग आंकड़ों से खेलते हैं, जबकि कुछ लोग असली नवाचार को प्राथमिकता देते हैं।” खड़गे ने व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि “कागज पर दिखाए गए अरबों डॉलर के निवेश तब तक वास्तविक नहीं होते जब तक वे धरातल पर उतर न जाएं।” इस तकरार के बाद दोनों राज्यों के समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। आंध्र के लोगों ने लोकेश का समर्थन करते हुए कहा कि विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति तेजी से आईटी उद्योग के नए केंद्र बन रहे हैं। वहीं कर्नाटक के यूजर्स ने खड़गे के पक्ष में यह तर्क दिया कि बेंगलुरु अब भी देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कैपिटल है, जहां विश्व की 400 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियों के अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धा तकनीकी रूप से लाभदायक भी है, क्योंकि इससे निवेशकों को बेहतर विकल्प मिलते हैं और दक्षिण भारत का आईटी इकोसिस्टम मजबूत होता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी चेताया कि इस प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सहयोग में बदलना अधिक उपयोगी होगा। दिलचस्प बात यह है कि गूगल का 15 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है और केंद्र सरकार की मंजूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे दिग्गजों के साथ नई साझेदारियों की घोषणा कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, नारा लोकेश और प्रियांक खड़गे दोनों युवा नेता हैं और अपने-अपने राज्यों में तकनीकी विकास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में दिखाया दम, मुनाफा 18,165 करोड़ रुपये

(जीएनएस)। मुंबई। भारत की अग्रणी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजे जारी किए, जिनमें कंपनी के मजबूत प्रदर्शन की झलक साफ दिखाई दी। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 15.9% बढ़कर 22,146 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 19,101 करोड़ रुपये था। ग्रॉस रेवेन्यू 9.9% की बढ़ोतरी के साथ 2,83,548 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी के सभी प्रमुख सेगमेंट—जियो, रिटेल और ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C)—ने मजबूती से योगदान दिया। कुल EBITDA 14.6% बढ़कर 50,367 करोड़ रुपये रहा। मुकेश अंबानी ने इस प्रदर्शन को चुस्त रणनीति, घरेलू बाजार पर फोकस और भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का परिणाम बताया।

जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस तिमाही में 14.9% की वृद्धि के साथ 42,652 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। EBITDA 17.7% बढ़कर 18,757 करोड़ रुपये रहा। जियो का सब्सक्राइबर बेस 506 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि जियो एयरफाइबर के माध्यम से हर महीने करीब 10 लाख नए घर जुड़े। कुल डेटा ट्रैफिक में 29.8% की बढ़ोतरी हुई। आकाश अंबानी ने कहा कि जियो ने 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों की डिजिटल जरूरतों को पूरा किया है और कंपनी का स्वदेशी तकनीकी स्टैक अब वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।

रिटेल कारोबार में भी मजबूत ग्रोथ देखी गई। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का राजस्व 18% बढ़कर 90,018 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 16.5% बढ़कर 6,816 करोड़ रुपये रहा। ग्रॉसरी और फैशन एवं लाइफस्टाइल में क्रमशः 23% और 22% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कंपनी ने 412 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर संख्या 19,821 तक पहुंच गई।

O2C सेगमेंट का राजस्व 3.2% बढ़ा और EBITDA 20.9% बढ़कर 15,008 करोड़ रुपये रहा। जियो-बीपी ने ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में 34% वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की। वहीं, ऑयल एंड गैस सेगमेंट का राजस्व 2.6% घटा, जिसका कारण KGD6 ब्लॉक में प्राकृतिक गिरावट और कंडेन्सेट कीमतों में कमी बताया गया।

कंपनी का टैक्स खर्च 17.6% बढ़कर 6,978 करोड़ रुपये और वित्तीय लागत 13.5% बढ़कर 6,827 करोड़ रुपये रही। इस तिमाही में कैपेक्स 40,010 करोड़ रुपये रहा, जिसका उपयोग O2C विस्तार, जियो नेटवर्क, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल फुटप्रिंट और न्यू एनर्जी गीगा फैक्ट्रियों में निवेश के लिए किया गया।

सितंबर 2025 के अंत तक रिलायंस का कुल कर्ज 3,48,230 करोड़ रुपये और नकद राशि 2,29,685 करोड़ रुपये रही। नेट डेब्ट-टू-EBITDA अनुपात 0.59 पर बना, जो कंपनी की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी न्यू एनर्जी, मीडिया और कंज्यूमर ब्रांड्स जैसे नए ग्रोथ इंजन पर तेजी से काम कर रही है और AI एवं नई तकनीक के जरिए भारत को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में अग्रसर है।

रिलायंस का यह प्रदर्शन निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के लिए भरोसेमंद संकेत माना जा रहा है कि कंपनी हर सेगमेंट में संतुलित ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की नोकझोंक से विकास की चर्चा अक्सर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है।

फिलहाल, इस डिजिटल जंग ने दोनों राज्यों के बीच “टेक्नोलॉजी रेस” को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।